रश्मि मेटालिक्स लिमिटेड व अन्य

बनाम

कोलकत्ता मेट्रोपोलियन विकास प्राधिकरण व अन्य

दीवानी अपील नंबर 6772/2013

11 सितम्बर, 2013

[टी.एस. ठाकुर और विक्रमजीत सेन, जे.जे.]

निविदा, निविदा की शर्तों में से एक का अनुपालन न करने के आधार पर बोली को अस्वीकार करना जो कि नवीनतम आयकर रिटर्न दाखिल करना - माना गया: आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक नहीं था, बल्कि केवल एक अतिरिक्त शर्त थी - इसलिए इस आधार पर बोली को अस्वीकार करना उचित नहीं है।

निविदा, बोली की अस्वीकृति - निविदा की शर्तों में से एक का पालन न करने के आधार पर प्राधिकरण द्वारा - निचली अदालतों ने भी उस आधार पर अस्वीकृति को बरकरार रखा और किसी अन्य शर्त के गैर-अनुपालन पर चर्चा या विश्लेषण नहीं किया - सुप्रीम कोर्ट में अपील में याचिका में एक अन्य शर्त के अनुपालन न करने के आधार की दलील दी- माना गया: पक्षकार उस आधार पर विज्ञापन नहीं कर सकते, जिस आधार पर निविदा प्राधिकारी ने विज्ञापन नहीं दिया था - एक पक्षकार को अपने

(पिछले फैसले में अपनाए गए रुख से परे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती - नई दलील उजागर करना - अनुज्ञेता।

नजीर - पूर्व निर्णय सिद्धांत घूरना निर्णय का सिद्धांत - माना गया: घूरना निर्णय के सिद्धांत की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि निर्णय समय के हमले का सामना करता है और उच्च अधिकार में बदल जाता है, श्रद्धा और पालन की मांग करता है।

अभ्यास और प्रक्रिया - अदालती कार्यवाही - अनेक निर्णयों का हवाला देने का अभ्यास - माना जाता है: इसके परिणामस्वरूप न्यायालयों का कीमती समय व्यर्थ हो जाता है - सही दृष्टिकोण उन निर्णयों पर तर्क प्रस्तुत करना है जो क्षेत्र को प्रभावित करते हैं।

अपीलकर्ता कंपनी की बोली को इस आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था कि उसने निविदा आमंत्रण के खंड 'जे' में उल्लिखित शर्तों का पालन नहीं किया था, जिसके तहत बोली लगाने वाले को अपनी नवीनतम आय प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।

नीचे की अदालतों ने माना कि अपीलकर्ता-कंपनी दो मामलों में निविदा की आवश्यक शर्तों का व्यापक रूप से पालन करने में विफल रही: (ए) निविदा के खंड (i) में बताए गए अनुसार अपीलकर्ता-कंपनी की कथित ब्लैकलिस्टिंग और (बी) खंड (जे) में परिकल्पित अनुसार नवीनतम

आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने में कंपनी की विफलता। हालाँकि, अदालतों ने खंड (i) की प्रयोज्यता और प्रासंगिकता का विश्लेषण नहीं किया।

इस न्यायालय में अपील में, प्रतिवादी ने खंड (जे) के अलावा खंड (i) के कथित उल्लंघन को भी उठाया।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया

1. जहां तक नोटिस की निविदा के आधार पर अस्वीकृति का संबंध है, यह मुद्दा पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गया है क्योंकि यह विवादित अस्वीकृति के कारण के रूप में शामिल नहीं है। इस आधार को शुरुआत में ही स्पष्ट किया जाना चाहिए था, और अब प्राधिकरण या किसी भी प्रतिवादी के लिए मुकदमेबाजी के इस स्तर पर पहली बार इस आधार को अपनाना उचित या स्वीकार्य नहीं है। आक्षेपित निर्णय निस्संदेह एक गूढ निर्णय है और इसमें वे कारण शामिल नहीं हैं जिन पर यह निर्णय आधारित है। चूँकि आक्षेपित निर्णय में कारण शामिल नहीं हैं, इसलिए इसे इस संक्षिप्त आधार पर अलग रखा जाना चाहिए कि किसी पक्ष को अपने पहले के निर्णय में अपनाए गए और व्यक्त किए गए रुख से परे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। [पैरा 12] [358-ई-जी]

मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली एआईआर 1978 एससी 851: 1978 (2) एससीआर 272 - पर भरोसा किया गया।

2. ई-निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस का खंड (जे) विषय एनआईटी का एक आवश्यक तत्व या घटक या सहवर्ती नहीं है। सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता-कंपनी द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल किया गया है। इनकम टैक्स शून्य था, लेकिन काफी टैक्स जमा किया गया था। आयकर रिटर्न आवश्यक शरतों में से एक होता यदि सकल आय अथवा शुद्ध आय पर कर लगाया होता तो आयकर रिटर्न एक आवश्यक शब्द का चरित्र ग्रहण कर लेता। कई मामलों में यह एक लाभकारी शर्त है, क्योंकि यह निविदा इकाई की व्यावसायिक स्थिति और विश्वसनीयता का संकेतक है। यह सुविधा नहीं होने के कारण, हम सोचते हैं कि नवीनतम आयकर रिटर्न दाखिल करना एक संपार्श्विक शर्त थी, और तदनुसार निविदा प्राधिकरण को इस विसंगति को अपीलकर्ता कंपनी के ध्यान में लाना चाहिए था और यदि उसके बाद भी कोई सुधार नहीं किया गया था, स्थिति काफ़ी भिन्न हो सकती थी। अपीलकर्ता कंपनी की ओर से यह दावा किया गया है, और प्रतिवादी-प्राधिकरण द्वारा इनकार नहीं किया गया है, कि अपीलकर्ता कंपनी की वित्तीय बोली अन्य की तुलना में काफी कम है, और इसलिए, आर्थिक रूप से बेहतर है। अपनी बोली के साथ नवीनतम आयकर रिटर्न जमा करने में विफल रहने के आधार पर अपीलकर्ता-कंपनी की अयोग्यता उसके प्रस्ताव/बोली की अवहेलना करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। [पैरा 13 और 14] [359-एफ-एच; 360-ए-डी]

पश्चिम बंगाल. राज्य विद्युत बोर्ड बनाम पटेल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (2001) 2 एससीसी 451: 2001 (1) एससीआर 352; टाटा सेल्यूलर बनाम भारत संघ (1994) 6 एससीसी 651; सीमेंस पब्लिक कम्युनिकेशन जी नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ (2008) 16 एससीसी 215: 2008 (15) एससीआर 585 - पर निर्भर।

सोरथ बिल्डर्स बनाम श्रीजीकृपा बिल्डकॉन लिमिटेड (2009) 11 एससीसी 9: 2009 (2) एससीआर 893 - संदर्भित।

कन्हैया लाल अग्रवाल बनाम भारत संघ (2002) 6 एससीसी 315: 2002 (1) पूरक एससीआर 284; पूर्वांकरा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड वी. होटल वीनस इंटरनेशनल (2007) 10 एससीसी 33: 2007 (2) एससीआर 215; ग्लोडाइन टेक्नोसर्व लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2011) 5 एससीसी 103: 2011 (15) एससीआर 930; पोद्दार स्टील बी कॉर्पोरेशन बनाम गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स (1991) 3 एससीसी 273: 1991 (2) एससीआर 696 - उद्धृत।

3.1. पूर्वता का नियम, जो न्यायशास्त्र का एक अभिन्न अंग है, आदेश देता है कि कानून के प्रदर्शन का पालन और कार्यान्वयन समन्वय या समान पीठों और निश्चित रूप से सभी छोटी पीठों और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भी किया जाना चाहिए। यदि एक समन्वय पीठ पिछली

पीठ के अनुपात निर्णय को संदिग्ध प्रभावकारिता मानता है, उसे मुख्य न्यायाधीश से एक बड़ी पीठ गठित करने का अनुरोध करने के अनुशासन का पालन करना चाहिए। इसके अलावा, एकल न्यायाधीश के फैसलों के भी कुछ उदाहरण हैं, जिन्होंने इन बातों का सामना किया है। समय के साथ, अपनी विशिष्टता और बेंच की शक्ति के विपरीत अनुसरण करने के कारण सम्मान और पालन की मांग करने वाले उच्च प्राधिकारी में रूपांतरित हो गए हैं। यह घूरने के निर्णय के सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। पूर्वता और घूरने के निर्णय का कानून इस पर आधारित_है एक मजबूती से स्थापित कानून प्रदान करने की बुद्धिमत्ता और लाभप्रदता, जिसके बिना अनिश्चितता और अस्पष्टता समाज में घबराहट पैदा कर सकती है। कानूनी पूर्वानुमान लगाना आवश्यक है। [पैरा 6] [353-डी-एच]

3.2. कानून के किसी विशेष बिंदु पर असंख्य निर्णयों का हवाला देने की प्रथा के कारण इस न्यायालय और इससे भी अधिक उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों को प्रत्येक मामले में लंबी बहस का सामना करना पड़ता है। यह अदालत के समय की बड़ी बर्बादी है, जिसकी कमी करना गंभीर हो गई है। सही दृष्टिकोण उस निर्णय पर तर्क प्रस्तुत करना है जो परिधि में आते हैं। [पैरा 6 और 7] [353-बी-सी; 354-सी]

केस कानून संदर्भ

2001 (1)एससीआर 352	भरोसा किया	पैरा 5

2002 (1)पूरक एससीआर 284	उद्धृत	पैरा 5
2007 (2) एससीआर 215	उद्धृत	पैरा 5
2011 (15) एससीआर 930	उद्धृत	पैरा 5
1991 (2) एससीआर 696	उद्धृत	पैरा 5
(1994) 6 एससीसी 651	भरोसा किया	पैरा 6
2008 (15) एससीआर 585	भरोसा किया	पैरा 6
2009 (2) एससीआर 893	संदर्भित किया	पैरा 6
1978 (2) एससीआर 272	भरोसा किया	पैरा 12

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल याचिका सं. 6772/2013

कलकत्ता उच्च न्यायालय के मैट नंबर 1031/2013 में के निर्णय और आदेश दिनांक 11.07.2013 से।

अपीलकर्ताओं के लिए विश्वनाथन, जॉयदीप मजूमदार, रोहित दत्ता, शिबाशीष मिश्रा, समीना, प्रभात कुमार श्रीवास्तव।

उत्तरदाताओं के लिए डॉ. ए. एम. सिंघवी, श्याम दीवान, प्रदीप घोष, संजीव के. कपूर, नितीश मैसी, खेतान एंड कंपनी, अनिंदिता गुप्ता, राजेश श्रीवास्तव।

न्यायालय का निर्णय विक्रमजीत सेन, जे. सुनाया गया।

1. हमें डिवीजन बेंच के आक्षेपित निर्णय की सत्यता का निर्णय करने के लिए बुलाया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बदले में उस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मामले के तथ्यों के साथ-साथ कानून की सराहना को बरकरार रखा है। इस प्रकार, इन अदालतों ने समवर्ती रूप से निष्कर्ष निकाला है कि अपीलकर्ता-कंपनी निविदा की आवश्यक शर्तों का व्यापक रूप से पालन करने में विफल रही है और इसलिए, उक्त निविदा में शामिल उसका प्रस्ताव विचार के लिए अयोग्य था।

2. 'निविदा के लिए निमंत्रण' विषय के दो शब्द जो मौजूदा मामले से संबंधित हैं, वे खंड (i) और 0 हैं, जो इस प्रकार हैं -

> "(i) एक गैर-न्यायिक स्टांप पेपर में शपथ पत्र के रूप में एक घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि आवेदक किसी भी सरकारी विभाग/ सरकारी उपक्रम / वैधानिक निकाय / नगर पालिका और इसी तरह के सरकारी निकायों द्वारा वर्जित / असूचीबद्ध / ब्लेक लिस्ट में नहीं डाला गया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान डीआई पाइप-आपूर्ति निविदा में और यदि किसी भी समय ऐसी कोई घटना पाई जाती है, तो निविदा बिना कोई कारण बताए सरसरी तौर पर रद्द कर दी जाएगी।

(ii) वैध पैन नंबर, वैट नंबर, नवीनतम आय की पावती की प्रति। टैक्स रिटर्न और प्रोफेशनल टैक्स रिटर्न।"

3. यह तुरंत स्पष्ट किया जाना चाहिए कि जहां तक खंड (i) का संबंध है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने इसकी प्रयोज्यता और प्रासंगिकता का विश्लेषण करना अनावश्यक समझा था, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि खंड क्यू का उल्लंघन किया गया है। अपीलकर्ता-कंपनी, क्योंकि वह अपनी बोली के साथ अपना नवीनतम आयकर रिटर्न दाखिल करने में विफल रही थी। जैसा कि आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाएगा, यह स्थिति डिवीजन बेंच के समक्ष भी प्राप्त होती रही है। खंड ii पर ध्यान देने के बावजूद, डिवीजन बेंच ने खुद को केवल खंड (i) के कथित गैर-अनुपालन से उत्पन्न होने वाले कानूनी निहितार्थों के बारे में चिंतित किया है। डिवीजन बेंच ने अपना फैसला डब्ल्यू.बी. पर आधारित किया है। राज्य विद्युत बोर्ड बनाम पटेल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (2001) 2 एससीसी 451 और जैसा कि हम भी करेंगे, उसमें से निम्नलिखित पैराग्राफ निकाले हैं -

"23. यह कहा गया है कि प्रश्न में गलतियाँ/त्रुटियाँ अनजाने में हुई हैं और कंप्यूटर की गलती के कारण हुई हैं, जिसे "दोहरावदार व्यवस्थित कंप्यूटर टाइपोग्राफ़िकल ट्रांसमिशन विफलता" कहा जाता है। इस तर्क को स्वीकार करना

मुश्किल है। एक गलती एकतरफा हो सकती है या आपसी लेकिन यह हमेशा अनजाने में होता है। यदि यह जानबूझकर किया गया है तो यह गलती नहीं रह जाती है। यहां गलतियाँ अनजाने में हो सकती हैं लेकिन बोली जमा करने से पहले इसे ठीक करना उत्तरदाताओं 1 से 4 के नियंत्रण से परे नहीं था। यदि वे सतर्क होते बोली दस्तावेजों को जमा करने से पहले जांचने से गलतियों से बचा जा सकता था। इसके अलावा, बोलियां खुलने के डेढ़ महीने के बाद ऐसी गलतियों को सुधारना भी आईटीबी के खंड 24.1, 24.3 और 29.1 का उल्लंघन होगा।

24. इस मामले में विवाद दहलीज पर खड़ा हो गया है. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली है जो गहरी प्रतिस्पर्धा और उच्च दक्षता को दर्शाती है। बोलीदाताओं को तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता मिलनी चाहिए या होनी चाहिए। ऐसी बोली में आवश्यक देखभाल का स्तर छोटे के लिए सामान्य स्थानीय बोलियों की तुलना में अधिक होता है! काम करता है. निविदा/बोली की प्रक्रिया और अनुबंध देने की पवित्रता और अखंडता को बनाए रखना आवश्यक है। अपीलकर्ता,

प्रतिवादी 1 से 4 और प्रतिवादी 10 और 11 सभी ITB से बंधे हैं जिनका ईमानदारी से अनुपालन किया जाना चाहिए। इस प्रकृति और परिमाण की स्थिति में, जहां केवल पूर्व अर्हता को पूरा करने वाले बोलीदाताओं को बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, निर्देशों के पालन को पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में ब्रांड करके नहीं दिया जा सकता है, अन्यथा यह भेदभाव, मनमानी को प्रोत्साहित करेगा और गुंजाइश प्रदान करेगा। और पक्षपात जो पूरी तरह से कानून के शासन और हमारे संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है। निर्देश जारी करने का उद्देश्य उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है ताकि कानून का शासन हताहत न हो। किसी नियम या शर्त में छूट या छूट, जब तक कि ITB के तहत राज्य या उसकी एजेंसियों (अपीलकर्ता) द्वारा एक बोलीदाता के पक्ष में प्रदान नहीं की जाती है, अन्य बोलीदाताओं के मन में उचित संदेह पैदा करेगी, पारदर्शिता और निष्पक्षता के नियम को ख़राब कर देगी और इनाम या दान वितरित करने के मामले में अनुबंध देने के लिए बोली लगाने वाले को चुनने और चुनने में राज्य एजेंसियों की इच्छा के अनुरूप हेरफेर के लिए जगह प्रदान करें, हमारे विचार में

इस तरह के दृष्टिकोण से हमेशा बचना चाहिए। जहां किसी नियम या शर्त को शिथिल करने या माफ करने की शक्ति नियमों के तहत मौजूद है, वहां इसे नियमों के अनुपालन में सख्ती से किया जाना चाहिए। इसलिए, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई झिझक नहीं है कि आईटीबी या नियमों का पालन करना सर्वोत्तम सिद्धांत है, जो सर्वोत्तम सार्वजनिक हित में भी है।"

4. आक्षेपित निर्णय में कहा गया है कि खंड (जे) को एक गैर-आवश्यक शब्द के रूप में नहीं देखा जा सकता है और इसलिए, निविदा जमा करने से पहले इसे ठीक किया जाना चाहिए था। यह हमें कालानुक्रमिक या क्रमिक रूप से असंभव लगता है; स्पष्ट रूप से इसका मतलब यह था कि इस नियम का पालन करने में विफलता बोली को गैर-अनुपालक बना देगी और इसलिए, पूरी तरह से विचार की सीमा से परे हो जाएगी। डिवीजन बेंच ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता-कंपनी को इस त्रुटि को ठीक करने की छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि 'ऐसी सुविधा अन्य बोलीदाताओं के लिए उपलब्ध नहीं थी।' हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा कहकर डिवीजन बेंच ने अपने उस विचार को कमजोर कर दिया है कि खंड (जे) पूरी तरह से अनुलंघनीय है।

5. उत्तरदाताओं ने खंड (i) के कथित उल्लंघन को हमारे सामने उठाने का प्रयास किया है, लेकिन हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रयास को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए। यह इस तथ्य के बावजूद है कि श्री के.वी. द्वारा इस संदर्भ में एक स्पष्टीकरण भी पेश किया गया है। अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील विश्वनाथन ने कहा। हम इस खंड उल के संबंध में कोई भी टिप्पणी करने से बचेंगे क्योंकि यह नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों के विश्लेषण में शामिल नहीं है। डॉ. ए.एम. सिंघवी, प्रतिवादियों के वरिष्ठ वकील ने हमारे सामने निम्नलिखित मामलों का हवाला दिया है: (i) डब्ल्यू.बी. राज्य विद्युत बोर्ड बनाम पटेल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (2001) 2 एससीसी 451 पैराज 23; (ii) कन्हैया लाल अग्रवाल बनाम भारत संघ (2002) 6 एससीसी 315 पैराग्राफ 5 और 6; (iii) पूर्वांकरा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम होटल वीनस इंटरनेशनल (2007) 1 सी' एससीसी 33 पैरा 28 से 30; (iv) सोरथ बिल्डर्स बनाम श्रीजीकृपा बिल्डकॉन लिमिटेड (2009) 11 एससीसी 9 पैराज 17 और 28; और (v) ग्लोडाइन टेक्नोसर्व लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2011) 5 एससीसी 103 पैरा 47। अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विश्वनाथन ने पोद्दार स्टील कॉर्पोरेशन बनाम गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स (1991) 3 एससीसी पर भरोसा करने की मांग की। 273 एवं कन्हैया लाल।

6. कानून के किसी विशेष बिंदु पर असंख्य निर्णयों का हवाला देने की प्रथा के कारण इस न्यायालय और इससे भी अधिक उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों को प्रत्येक मामले में लंबी बहस का सामना करना पड़ता है। सही दृष्टिकोण विधेय करना है निर्णय पर तर्क जो क्षेत्र को धारण करता है, जो वर्तमान मामले में टाटा सेल्युलर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1994) 6 एससीसी 651 है, जो तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्राथमिकता का नियम, जो हमारे न्यायशास्त्र का एक अभिन्न अंग है, आदेश देता है कि कानून की इस व्याख्या का पालन और कार्यान्वयन समन्वित या सह-समान पीठों और निश्चित रूप से सभी छोटी पीठों और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भी किया जाना चाहिए। हम यह स्पष्ट करने में जल्दबाजी करते हैं कि यदि कोई समन्वय पीठ पिछली पीठ के अनुपात निर्णय को संदिग्ध प्रभावकारिता मानती है, तो उसे माननीय मुख्य न्यायाधीश से एक बड़ी पीठ गठित करने का अनुरोध करने के अनुशासन का पालन करना चाहिए। इसके अलावा एकल न्यायाधीश के फैसलों के भी कुछ उदाहरण हैं, जो समय के थपेड़ों का सामना करते हुए अपनी विशिष्टता और पीठ की ताकत के विपरीत अनुसरण के कारण सम्मान और अनुपालन की मांग करते हुए उच्च प्राधिकारी में बदल गए हैं। यह घूरने के निर्णय के सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दशकों से, सरकारी निविदाओं और अनुबंधों से संबंधित लगभग हर मामले में टाटा सेल्युलरी

का इतना सर्वव्यापी अनुसरण किया गया है कि इसने ऐसी ऊंचाइयां हासिल कर ली हैं जो एक बड़ी बेंच को भी विषयांतर करने से रोकती हैं। पूर्वता और निर्णायक निर्णय का कानून एक मजबूती से स्थापित कानून प्रदान करने की बुद्धिमत्ता और श्रेष्ठता पर आधारित है, जिसके बिना अनिश्चितता और अस्पष्टता समाज में घबराहट पैदा कर सकती है। यह कानूनी पूर्वानुमेयता प्राप्त करता है, जिसे सीधे तौर पर कहा गया है, यह एक आवश्यक है। हमारे शोध से केवल एक अन्य तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के अस्तित्व का पता चला है, जिसने कानून के इस पहलू से निपटा है, अर्थात् सीमेंस पब्लिक कम्युनिकेशन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ (2008) 16 एससीसी 215, जो वास्तव में एक संकलन है टाटा सेल्यूलर सहित पिछले सभी निर्णयों की। उदाहरणों की प्रचुरता यह आवश्यक बनाती है कि इस न्यायालय को कानून के समान प्रश्न से निपटने वाले प्रत्येक निर्णय पर चर्चा करने से बचना चाहिए। इस अनुशासन और व्यवस्था का पालन करने में विफलता से निर्णयों में विलंब होता है जो हमेशा लंबी बहस का परिणाम होता है।

7. यह न्यायालय के मूल्यवान समय की बर्बादी है, जिसमें कमी करना काफी गंभीर हो गया है। इसलिए, हम खुद को टाटा सेल्यूलर तक ही सीमित रखेंगे। हम इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि यह एक वैध अभ्यास है, जो कानून को आगे बढ़ाने के लिए बेंचों के लिए पूरी तरह से

स्वीकार्य है, बशर्ते कि यह अभ्यास किसी ऐसे निष्कर्ष पर न पहुंचे जो बाध्यकारी मिसाल के साथ असंगत हो। हम यह भी स्पष्ट करेंगे कि जिस तरह से एक बेंच पहले तथ्यात्मक मैट्रिक्स की सराहना करती है वह स्पष्ट रूप से केवल तभी मूल्यवान हो सकती है जब बाद का मामला समान तथ्य प्रस्तुत करता है, जो दुर्लभ है।

8. टाटा सेल्यूलर इस प्रकार कहता है:

"77. न्यायालय का कर्तव्य स्वयं को वैधानिकता के प्रश्न तक ही सीमित रखना है। उसकी चिंता यह होनी चाहिए:

1. क्या निर्णय लेने वाला प्राधिकारी अपनी शक्तियों से आगे निकल गया है?

2. कोइ विधिक त्रुटि की गइ हो

3. प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन किया,

4. ऐसे निर्णय पर पहुंचा जिस पर कोई भी उचित न्यायाधिकरण नहीं पहुंच पाता या,

5. अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया।

इसलिए, यह निर्धारित करना न्यायालय का काम नहीं है कि कोई विशेष नीति या उस नीति की पूर्ति में लिया गया विशेष निर्णय उचित है या नहीं। इसका संबंध केवल इस

बात से है कि ये निर्णय किस तरीके से लिए गए हैं। निष्पक्ष रूप से कार्य करने के कर्तव्य ए1 की सीमा हर मामले में अलग-अलग होगी। संक्षेप में कहें तो, जिन आधारों पर प्रशासनिक कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के नियंत्रण के अधीन है, उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

(i) अवैधता: इसका मतलब है कि निर्णय लेने वाले को उस कानून को सही ढंग से समझना चाहिए जो उसकी निर्णय लेने की शक्ति को नियंत्रित करता है और उसे प्रभावी बनाना चाहिए।

(ii) अतार्किकता, अर्थात्, बुधवारबरी अतार्किकता।

(iii) प्रक्रियात्मक अनौचित्य।

उपरोक्त केवल व्यापक आधार हैं लेकिन यह समय के साथ और आधार जुड़ने से इंकार नहीं करता है। वास्तव में, आर. बनाम गृह विभाग के राज्य सचिव, एकपक्षीय ब्रिंड, (1991) 1 एसी 696 में, लॉर्ड डिप्लॉक विशेष रूप से एक विकास को संदर्भित करता है, अर्थात् आनुपातिकता के सिद्धांत की संभावित मान्यता। इन सभी मामलों में अपनाई जाने वाली कसौटी यह है कि न्यायालय को विचार करना चाहिए कि

क्या कुछ प्रकृति और स्तर की गलत हुई है जिसके लिए उसके हस्तक्षेप की आवश्यकता है।"

संविदात्मक कानून में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है; तथ्यों के आधार पर इस न्यायालय ने माना कि चूंकि दस्तावेज़ निर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार नहीं भेजे गए थे, इसलिए जो बोली पहले ही ऑनलाइन प्राप्त हो चुकी थी, उस पर सही ढंग से विचार नहीं किया जा सका। ग्लोडाइन टेक्नोसर्व टाटा सेल्युलर पर भी लागू होता है; लेकिन तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर जहां तक उत्तरदाताओं का सवाल है, जो इस पर भरोसा करते हैं, यह असंगत लगता है, क्योंकि यह मानता है कि यह संबंधित प्राधिकारी के विवेकाधीन क्षेत्र में आता है कि दस्तावेजों पर विचार किया जाए या नहीं (उस मामले में एक आईएसओ प्रमाणन) जो कि निविदा शर्तों के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया गया था। श्री विश्वनाथन के भरोसेमंद कन्हैया लाल उसी लय में बात करते हैं जिसमें वह निविदा की आवश्यक और सहायक शर्तों के बीच अंतर करते हैं और बाद के मामले में विवेक के प्रयोग के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करते हैं। हालाँकि इसे वेडनसबरी की तर्कसंगतता के एक पहलू के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इस निर्णय को टाटा सेल्युलर में एक और कारक जोड़ने के रूप में देखा जा सकता है, अर्थात, न्यायालय को गेहूं को भूसी से अलग करने का अधिकार है। इस अभ्यास में न्यायालय कॉम्पैक्ट की आधारशिला बनाने वाली आवश्यक शर्तों

को अलग कर सकता है, और उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए, संपार्श्विक धाराओं के अनुपालन के प्रति उदारता की अनुमति दे सकता है। उद्धृत केस-कानून के इस विश्लेषण से पता चलता है कि जिस तरह से न्यायालय ने तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर प्रतिक्रिया दी है, उससे बहुत कम या कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि अन्य न्यायालय एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए वैध रूप से समान तथ्यों पर जोर दे सकते हैं। लेकिन अनुपात निर्णय का पालन किया जाना चाहिए। इसलिए वकील को उन मामलों में से एक में सावधानी बरतनी चाहिए जो वे उद्धृत करते हैं। टाटा सेल्युलर में तीन न्यायाधीशों वाली बेंच निविदाओं से संबंधित कानून पर विचार करने के लिए पर्याप्त से अधिक है; बाद के निर्णय सीमेंस में समन्वय पीठ इस मुद्दे पर पिछले निर्णयों के इतिहास की प्रकृति में है।

10. बार में उद्धृत निर्णयों के इस संक्षिप्त विश्लेषण के साथ, अब हम उन आवश्यक कारकों पर लौटेंगे जो हमारे निर्णय को निर्धारित करेंगे। जिन दो खंडों पर हमारे सामने बहस हो चुकी है, उन्हें हम पहले ही ऊपर प्रस्तुत कर चुके हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष वापस कर दिया था कि अपीलकर्ता-कंपनी की निविदा दो मामलों में 'निविदा के निमंत्रण' की आवश्यक शर्तों के अनुरूप नहीं थी:

(ए) अपीलकर्ता-कंपनी की कथित ब्लैकलिस्टिंग जैसा कि खंड (i) में बताया गया है; और

(बी) अपीलकर्ता-कंपनी की नवीनतम आयकर रिटर्न प्रस्तुत/अग्रेषित करने में विफलता, जैसा कि खंड (जे) में परिकल्पित है।

11. अपीलकर्ता-कंपनी के प्रस्ताव को अस्वीकार करने वाला पत्र इस प्रकार है:

"विषय: केएमडीए: निविदा संख्या: 01/केएमडीए/मैट/सीई/2013-2014 के लिए अयोग्य घोषित

दिनांक : सोमवार, 22 जुलाई 2013 18:13:22 +0530 (आईएसटी)

प्रेषक: टेंडर टेंडर@eterderwizard.com

प्रति: sales.marketingdomestic@rashmigroup.com

प्रिय राशि मेटालिक्स लिमिटेड,

महत्वपूर्ण सूचना:

सूचित किया जाता है कि आपकी बोली केएमडीए द्वारा आमंत्रित निविदा के लिए अयोग्य घोषित कर दी गई है

निविदा संख्या: 01/केएमडीए/मैट/सीई/2013-2014

लाइन नं.: 01

कार्य का नाम: कोलकाता मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के भीतर अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग व्यास वाले के 7 और के 9 पाइपों की आपूर्ति और वितरण अयोग्यता का कारण: कंपनी ने अपनी बोली के साथ अपना नवीनतम आयकर रिटर्न जमा नहीं किया है।

सस्नेह

निविदा प्राधिकारी"

12. जहां तक पहले बिंदु का सवाल है, इसे कम समय में निपटाने की जरूरत है क्योंकि नीचे के न्यायालयों ने इसे चर्चा के लिए प्रासंगिक नहीं समझा है, अपने विवेक से, अपीलकर्ता को गैर-अनुकूल बनाने के लिए इसे पर्याप्त माना है। -कंपनी को दूसरी बार विफलता के लिए। हालाँकि, अपीलकर्ता-कंपनी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विश्वनाथन द्वारा यह समझाया गया है कि वास्तविक समय में अपीलकर्ता-कंपनी को कोई ब्लैकलिस्टिंग या डीलिस्टिंग नहीं किया गया था और उन परिस्थितियों में कोई भी खुलासा करना प्रासंगिक नहीं था। इस संबंध में। तथ्य यह है कि टेंडरिंग अथॉरिटी ने 22 जुलाई 2013 के अपने संचार के संदर्भ में इस आधार पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, इस तर्क को बल देता है कि यदि इस आधार को उठाया गया था तो एक वैध तर्क पेश किया गया था। इस संबंध में अपीलकर्ता-कंपनी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के वजन, संक्षिप्तता या

पर्याप्तता के बावजूद, यह मुद्दा पूरी तरह से हमारे संज्ञान के लिए अप्रासंगिक हो गया है क्योंकि यह विवादित अस्वीकृति के कारण के रूप में शामिल नहीं है। इस आधार को शुरुआत में ही स्पष्ट किया जाना चाहिए था, और अब यह प्राधिकरण या किसी भी प्रतिवादी के लिए मुकदमेबाजी के इस दूसरे साल्वो में पहली बार एक साइड विंड के माध्यम से अपनाने के लिए फोरेंसिक रूप से उचित या स्वीकार्य नहीं है। आक्षेपित निर्णय निस्संदेह गूढ़ है और इसमें वे कारण शामिल नहीं हैं जिन पर निर्णय आधारित है। चूँकि आक्षेपित निर्णय में कारण शामिल नहीं हैं, इसलिए इसे इस संक्षिप्त आधार पर अलग रखा जाना चाहिए कि किसी पक्ष को अपने पहले के निर्णय में अपनाए गए और व्यक्त किए गए रुख से परे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली, एआईआर .1978 एससी 851 मामले में चर्चित फैसले में पाई गई निम्नलिखित टिप्पणियाँ इस प्रश्न के लिए प्रासंगिक हैं:

> "8. दूसरा समान रूप से प्रासंगिक मामला यह है कि जब कोई वैधानिक पदाधिकारी कुछ आधारों के आधार पर कोई आदेश देता है, तो उसकी वैधता का आकलन उल्लिखित कारणों से किया जाना चाहिए और इसे हलफनामे या अन्यथा के रूप में नए कारणों से पूरक नहीं किया जा सकता है। अन्यथा, एक शुरुआत में खराब आदेश, चुनौती

के कारण अदालत में आने तक, बाद में लाए गए अतिरिक्त आधारों द्वारा मान्य हो सकता है। हम यहां गोर्धनदास भानजी (एआईआर 1952 एससी 16) में बोस जे की टिप्पणियों पर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। (पृ.18 पर):

"वैधानिक प्राधिकार के प्रयोग में सार्वजनिक रूप से दिए गए सार्वजनिक आदेशों को आदेश देने वाले अधिकारी द्वारा बाद में दिए गए स्पष्टीकरणों के आलोक में नहीं समझा जा सकता है कि उसका क्या मतलब था, या उसके दिमाग में क्या था, या वह क्या करने का इरादा रखता था। सार्वजनिक सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा दिए गए आदेश सार्वजनिक प्रभाव के लिए होते हैं और उन लोगों के कार्य और आचरण को प्रभावित करने के लिए होते हैं जिन्हें वे संबोधित किए जाते हैं और उन्हें आदेश में प्रयुक्त भाषा के संदर्भ में निष्पक्ष रूप से समझा जाना चाहिए।

ऑर्डर पुरानी शराब की तरह नहीं हैं, जैसे-जैसे ऑर्डर बढ़ते हैं, वे बेहतर होते जाते हैं।"

13. जहां तक मुख्य अभियंता के कार्यालय से निकलने वाली ई-निविदा संख्या 01/केएमडीए/एमएटी/सीई/2013-2014 दिनांक 10.5;2013 को आमंत्रित करने वाले विस्तृत नोटिस के खंड उल का संबंध है, हमें ऐसा

लगता है कि यह इसके विपरीत है। आक्षेपित निर्णय में निष्कर्ष, खंड एनआईटी विषय का एक आवश्यक तत्व या घटक या सहवर्ती नहीं है। सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ता-कंपनी द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल किया गया है और हमारे द्वारा इसकी जांच की गई है। आकलन वर्ष 2011-2012 के लिए, अपीलकर्ता-कंपनी की सकल आय 15,34,05,627 रुपये थी, हालांकि, अगले आकलन वर्ष 2012-2013 के लिए, आयकर शून्य था, लेकिन पर्याप्त कर जमा किया गया था। हमारा मानना है कि यदि योग्यताओं में से एक सकल आय या शुद्ध आय थी, जिस पर कर लगाया गया था, तो आयकर रिटर्न एक आवश्यक शब्द का चरित्र ग्रहण कर लेता। कई मामलों में यह एक लाभकारी शर्त है, क्योंकि यह निविदा इकाई की व्यावसायिक स्थिति और विश्वसनीयता का संकेतक है। यह सुविधा अनुपस्थित होने के कारण, हमारा मानना है कि नवीनतम आयकर रिटर्न दाखिल करना एक संपार्श्विक शर्त थी, और तदनुसार निविदा प्राधिकरण को इस विसंगति को अपीलकर्ता-कंपनी के ध्यान में लाना चाहिए था और यदि उसके बाद भी कोई सुधार नहीं किया गया था, स्थिति काफ़ी भिन्न हो सकती थी। अपीलकर्ता-कंपनी की ओर से यह दावा किया गया है, और प्रतिवादी-प्राधिकरण के विद्वान वकील ने इसका खंडन नहीं किया है, कि अपीलकर्ता-कंपनी की वित्तीय बोली अन्य की तुलना में काफी कम है, और इसलिए, आर्थिक रूप से बेहतर है।

14. इस विश्लेषण में, हमने पाया कि अपील अच्छी तरह से स्थापित है और स्वीकार्य है। तदनुसार आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जाता है। अपनी बोली के साथ नवीनतम आयकर रिटर्न जमा करने में विफल रहने के आधार पर अपीलकर्ता-कंपनी की अयोग्यता उसके प्रस्ताव/बोली की अवहेलना करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। इसलिए, उत्तरदाताओं को इस पूर्वानुमान पर मामले में आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है। पक्षकार अपनी-अपनी लागत वहन करेंगे।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मनोज जीनगर (आर.जे.एस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।